जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

बनाम

बी. एस. नरवाल

4 सितंबर, 1980

[वी. आर. कृष्णा अय्यर और ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, न्यायाधिपतिगण]

विश्वविद्यालय- छात्र- अध्ययन में असंतोषजनक प्रदर्शन- विश्वविद्यालय की सूची से नाम हटा दिया गया- कारण दिखाने का अवसर कि क्या दिया जाना है- ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत- की प्रयोज्यता।

अपीलकर्ता विश्वविद्यालय ने कई विषयों और भाषाओं में एमए की डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के एकीकृत 5 साल के कार्यक्रम की पेशकश की। कार्यक्रम 5 शैक्षणिक वर्षों में दस सेमेस्टर में फैला हुआ था। जिस अनुशासन में एक छात्र को औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया था, उस पाठ्यक्रम को 'कोर-पाठ्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, जबकि अन्य पाठ्यक्रम जिनके लिए छात्र को भी निर्धारित करना पड़ता था, उन्हें 'टूल पाठ्यक्रम' और 'वैकल्पिक पाठ्यक्रम' के रूप में जाना जाता था।

प्रतिवादी अपीलकर्ता विश्वविद्यालय में रूसी भाषा में मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री में अध्ययन के पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का छात्र था।

पहले दो सेमेस्टर में, वह रूसी में किसी भी 'मुख्य पाठ्यक्रम' में सत्रीय परीक्षा देने में असफल रहे और परिणामस्वरूप उन्हें अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। हालाँकि, वह पहले दो सेमेस्टर में टूल कोर्स और वैकल्पिक कोर्स की परीक्षाओं में शामिल हुए। तीसरे सेमेस्टर में प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय से पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को दोहराने की अनुमति मांगी ताकि वह उन्हें उत्तीर्ण कर सके। विश्वविद्यालय ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी लेकिन वह उन सभी पाँच पाठ्यक्रमों में असफल हो गया जिनमें उसे ऐसा करने की अनुमति दी गई थी।

उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट होकर रूसी अध्ययन केंद्र ने अध्ययन बोर्ड को सिफारिश की कि प्रतिवादी का नाम सूची से हटा दिया जाए और तदनुसार उसका नाम सूची से हटा दिया जाए।

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि: (1) उसका नाम सूची से हटाने से पहले उसे कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और (2) विश्वविद्यालय ने प्रश्न पर अपना दिमाग नहीं लगाया था, क्या प्रतिवादी का प्रदर्शन असंतोषजनक था।

इस प्रश्न पर इस न्यायालय में अपील में: क्या प्रतिवादी को विश्वविद्यालय के रोल से हटाने से पहले, सुनवाई का अवसर पाने का हकदार था।

अपील को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया:

1. पूर्वाग्रह या दुर्भावना के आरोपों के अभाव में, एक शैक्षणिक निकाय द्वारा यह घोषणा कि एक छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन असंतोषजनक है, इस आधार पर अदालत में सवाल किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है कि छात्र को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। [623 ई-एफ]

यह किसी विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्र को अपने विवेक से अनुशासित करने और छात्र की स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार के दावे के अनुसार निष्कासन का मामला नहीं है। यह मामला केवल एक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन का है, जिसका मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय के निर्धारित प्राधिकारी सर्वोत्तम योग्य हैं और न्यायालय सबसे कम योग्य हैं। [623 ए-बी]

हेरिंग बनाम टेम्पलमेन एवं अन्य 1973 (3) सभी ई. आर. 569 और 584; रेजिना बनाम एस्टन यूनिवर्सिटी सीनेट 1969 (2) सभी ई.आर. 964- संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3115/1979

दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील, सिविल रिट संख्या 395/1979 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 6-8-1979 के निर्णय और आदेश से।

के.के. वेणुगोपाल, एच.के. पुरी और एस.सी. ढांडा, अपीलकर्ता के लिए।

ए.के. गुप्ता, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायाधिति द्वारा सुनाया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना जाता है, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय की विशेष अनुमति से इस अपील में अपीलकर्ता है। सदी के महान उदारवादी, मानवतावादी और लोकतंत्रवादी के नाम पर, विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा "मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक अद्वितीय संश्लेषण को मूर्त रूप देने" और "उन सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए की गई थी जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने उनके जीवनकाल के दौरान, अर्थात् राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, जीवन का लोकतांत्रिक तरीका, अंतर्राष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिये काम किया था।

"न्यायालय" विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी है और इसके पास कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति है। कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी और अकादमिक अधिकारी हैं। कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय है, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन का प्रभारी, जबकि अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय का शैक्षणिक निकाय है, जो विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षा, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। कार्यकारी परिषद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से 'क़ानून' बनाने और क़ानून द्वारा निर्धारित तरीके से 'अध्यादेश' बनाने का अधिकार है।

अध्यादेश विधिवत बनाए गए हैं और अध्यादेश 13 एमए, बी.ए., (ऑनर्स) और बी.ए. (पास) डिग्री के पुरस्कार से संबंधित है। विश्वविद्यालय कई विषयों और भाषाओं में एम.ए. डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के एकीकृत पांच-वर्षीय कार्यक्रम प्रदान करता है। रूसी उन भाषाओं में से एक है जिसमें इस तरह के अध्ययन कार्यक्रम की पेशकश की जाती है होता है, कार्यक्रम पांच शैक्षणिक वर्षों में दस सेमेस्टर में फैला हुआ है। पहले दो सेमेस्टर में 'सी' स्तर के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं, अगले चार सेमेस्टर में 'बी' स्तर के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं और अंतिम चार सेमेस्टर में 'ए' स्तर के पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। प्रत्येक 'सी' स्तर के पाठ्यक्रम में दो क्रेडिट, प्रत्येक 'बी' स्तर के पाठ्यक्रम में तीन क्रेडिट और प्रत्येक 'ए' स्तर के

पाठ्यक्रम में चार क्रेडिट होते हैं। अध्यादेश 13 का पैराग्राफ 7.3 मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री के लिए सामाजिक विज्ञान के मामले में न्यूनतम 144 क्रेडिट और भाषाओं के मामले में 176 क्रेडिट निर्धारित करता है, जिसमें से 'सी लेवल पाठ्यक्रम' से न्यूनतम 20 क्रेडिट होने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के मामले में 'बी' स्तर के पाठ्यक्रमों से 60 और 'ए' स्तर के पाठ्यक्रमों से 64 और 'सी' स्तर के पाठ्यक्रमों से न्यूनतम 28, 'बी' स्तर के पाठ्यक्रमों से 84 और 'ए' स्तर के पाठ्यक्रमों से 64, भाषाओं के मामले में। आगे यह निर्धारित किया गया है कि न्यूनतम 50% क्रेडिट लेकिन 75% से अधिक उस अनुशासन में नहीं होना चाहिए जिसमें छात्र औपचारिक रूप से मास्टर डिग्री के लिए पंजीकृत है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि जिस अनुशासन में छात्र औपचारिक रूप से पंजीकृत है, उस पाठ्यक्रम को 'कोर पाठ्यक्रम' के रूप में जाना जाता है, जबकि अन्य पाठ्यक्रम जिनके लिए छात्र को भी निर्धारित करना होता है, उन्हें "टूल पाठ्यक्रम' और 'वैकल्पिक पाठ्यक्रम' के रूप में जाना जाता है। पैराग्राफ 7.5 निर्धारित करता है कि जिन पाठ्यक्रमों के आधार पर एक छात्र अपने 'सी' स्तर के क्रेडिट अर्जित करता है, वे कम से कम चार विषयों से होंगे। पैराग्राफ 7.6 में प्रावधान है कि एक छात्र को टूल्स में पाठ्यक्रमों से कम से कम दस क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होगी, तकनीक और कार्यप्रणाली। अध्यादेश 13 का पैराग्राफ 8 मूल्यांकन की विधि निर्धारित करता है। सत्रीय कार्य को सेमेस्टर परीक्षा के समान महत्व देना है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक छात्र

को दस अंक के पैमाने पर ग्रेड दिया जाता है और अंतिम ग्रेड अंक सूत्र लागू करते हुये किया जाता है।

जहां एफ आई छात्र सी आई का अंतिम ग्रेड प्वाइंट है, यह कोर्स का क्रेडिट है, कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड प्वाइंट है और यह कुल पाठ्यक्रमों की संख्या है जिसके लिए छात्र ने निर्धारित किया है। जो छात्र किसी पाठ्यक्रम में असफल हो जाता है, उसे उस पाठ्यक्रम को दोहराना पड़ता है या उस पाठ्यक्रम के बदले में कोई अन्य पाठ्यक्रम पास करना पड़ता है, जिसमें वह असफल हुआ है। अध्यादेश का पैराग्राफ 9 ग्रेड प्वाइंट आवश्यकता के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। प्रत्येक छात्र को पहले दो सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 2.0 बनाए रखना आवश्यक है। यदि उसे अध्ययन के कार्यक्रम को आगे जारी रखना है तो छठे सेमेस्टर के अंत में संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत 4 होना चाहिए। वह अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री से सम्मानित होने के लिए उसके पास एक 4.0 का संचयी ग्रेड बिंदु औसत होना चाहिए। इस प्रकरण के प्रयोजन के लिये अध्यादेश का पैराग्राफ संख्या 11 महतवपूर्ण है और इसे यहां निकाला जा सकता है। जैसा कि प्रासंगिक समय पर था, यह इस प्रकार था:

"स्कूल का बोर्ड, केंद्र की सिफारिश पर, असंतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किसी छात्र का नाम पाठ्यक्रम से हटा सकता है।"

प्रतिवादी बी.एस. नरवाल को 1974 में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूसी अध्ययन केंद्र में रूसी भाषा में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अध्ययन के पांच साल के एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। चूँकि वह रूसी भाषा में डिग्री चाह रहे थे, इसलिए 'मुख्य पाठ्यक्रम' में आवश्यक रूप से रूसी भाषा, साहित्य और अनुवाद से संबंधित विषय होने चाहिए। पहले दो सेमेस्टर में, वह रूसी में किसी भी 'मुख्य पाठ्यक्रम' में सत्रीय परीक्षा देने में असफल रहे और परिणामस्वरूप उन्हें अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार वह पहले दो सेमेस्टर में किसी भी 'मुख्य पाठ्यक्रम' को पास करने में विफल रहा। हालाँकि, वह पहले दो सेमेस्टर में 'टूल' और 'वैकल्पिक पाठ्यक्रम' की परीक्षाओं में शामिल हुए और पहले सेमेस्टर में दो पाठ्यक्रमों में पांच क्रेडिट और दूसरे सेमेस्टर में तीन पाठ्यक्रमों में आठ क्रेडिट निर्धारित किए गए। तीसरे सेमेस्टर में प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय से पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को दोहराने की अनुमति मांगी ताकि वह उन्हें उत्तीर्ण कर सके। एक विशेष मामले के रूप में, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे उन सभी पांच पाठ्यक्रमों में असफल रहे, जिनके संबंध में उन्होंने ऐसा दोहराने की अनुमति मांगी थी और प्राप्त की

थी। हालाँकि, प्रतिवादी तीसरे सेमेस्टर में निर्धारित वैकल्पिक पाठ्यक्रम में (बी+ प्राप्त करके) उत्तीर्ण हुआ। तीसरे सेमेस्टर के अंत में नतीजा यह निकला कि उसने एक भी 'कोर कोर्स' पास नहीं किया।

रूसी अध्ययन केंद्र प्रतिवादी और कुछ अन्य छात्रों के प्रदर्शन से असंतुष्ट था और 20 जनवरी 1976 को आयोजित एक बैठक में, केंद्र ने अध्ययन बोर्ड, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज को सिफारिश करने का निर्णय लिया कि सात छात्रों में शामिल हैं- असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए प्रतिवादी को विश्वविद्यालय के रोल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। रूसी अध्ययन केंद्र की सिफारिश को विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया और 31 जनवरी, 1976 के एक कार्यालय आदेश द्वारा, केंद्र की सिफारिश के अनुसार असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए प्रतिवादी और अन्य को विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया।

ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय के फैसले को स्वीकार कर लिया और दो साल और छह महीने की अवधि तक चुप रहा, लेकिन अगस्त, 1978 में, उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उसे विश्वविद्यालय के रोल से हटाने के आदेश को चुनौती दी गई इस आधार पर कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके दिया गया था। रिट याचिका का विश्वविद्यालय द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन जब रिट याचिका 24 नवंबर, 1978 को

सुनवाई के लिए आई, तो न्यायालय ने यह पूछा कि क्या प्रतिवादी को फिर से प्रवेश देना संभव है, तो विश्वविद्यालय सहानुभूतिपूर्वक प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद रिट याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन के अनुसार रूसी अध्ययन केंद्र ने एक बार फिर प्रश्न पर विचार किया और खुद को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में प्रतिवादी को स्वीकार करने में असमर्थ पाया। हालाँकि, प्रतिवादी को सूचित किया गया था कि उसके मामले पर जुलाई 1979 से शुरू होने वाले मानसून सेमेस्टर में, यानी शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में विचार किया जा सकता है। प्रतिवादी को प्रवेश के लिए नया आवेदन भेजने की सलाह दी गई। प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय के रवैये से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में एक बार फिर नई रिट याचिका दायर की, जिसमें उसे विश्वविद्यालय के रोल से हटाने के आदेश को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले, दिनांक 6 अगस्त, 1979 द्वारा रिट याचिका को पहले तो इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि प्रतिवादी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और दूसरे इस आधार पर कि विश्वविद्यालय ने अपना दिमाग नहीं लगाया। सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता का प्रदर्शन असंतोषजनक था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को विश्वविद्यालय के नामावली से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय को निम्नलिखित निर्देश दिए:

"(1) कि याचिकाकर्ता बी.एस. नरवाल को 7वें सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना चाहिए जो कि 1979 का मानसून सेमेस्टर है;

(2) कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 1981 के अंत तक दस सेमेस्टर पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी एमए डिग्री प्राप्त करने के योग्य हो सके;

(3) कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 1981 के अंत तक आवश्यक 180 क्रेडिट सुरक्षित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और संपर्क घंटे, सत्र परीक्षण और सेमेस्टर परीक्षा और उसके 10वें सेमेस्टर के पूरा होने से पहले उपयुक्त सेमेस्टर की परीक्षाओ देकर अब तक हासिल किए गए क्रेडिट में कमी को पूरा करना चाहिए;

(4) कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता को आवश्यक पाठ्यक्रमों को लेने के लिए उचित समूहों में शामिल होने की अनुमति देगा और उचित अंतराल पर सत्र परीक्षाओं और सेमेस्टर परीक्षाओं की उचित व्यवस्था करेगा ताकि एक समय में बहुत अधिक शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा न किया जा सके।"

हमारे विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी विश्वविदयालय के रोल से हटाये जाने की कार्यवाही से पहले सुनवाई के अवसर का हकदार था। शुरुआत में ही इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह किसी विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा अपने विवेक से छात्र को अनुशासित करने और छात्र की स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार के दावे के आधार पर किसी छात्र के निष्कासन का मामला नहीं है। यह मामला महज एक छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के आकलन का है, जिसे आंकने के लिए विश्वविद्यालय के निर्धारित प्राधिकारी सबसे योग्य हैं और अदालतें शायद सबसे कम योग्य हैं। न ही सुनवाई का कोई अवसर दिए जाने का कोई सवाल ही पैदा हो सकता है। जब कोई उम्मीदवार किसी योग्यता या बुद्धि परीक्षण, लिखित या मौखिक में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो किसी दावे की सुनवाई नहीं होती है। जब विधिवत योग्य और सक्षम शैक्षणिक अधिकारी किसी छात्र के काम की समय-समय पर जांच और मूल्यांकन करते हैं और उसके काम को असंतोषजनक घोषित करते हैं तो हम यह देखने में असमर्थ होते हैं कि सुनवाई के अधिकार का कोई सवाल कैसे उठ सकता है। ऐसे मामले में एक अकादमिक निकाय का कर्तव्य छात्र के संपूर्ण रिकॉर्ड और क्षमता के आधार पर उसके काम के मानक का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। यही उनका कार्य है। शैक्षणिक निर्णय के कार्य की प्रकृति (यदि संदर्भ में निर्णय शब्द का उपयोग अनुमत है) हमें सुनने के अवसर के किसी भी अधिकार को नकारात्मक रूप से

प्रभावित करती प्रतीत होती है। यदि शैक्षणिक निकाय द्वारा मूल्यांकन गैर-शैक्षणिक परिस्थितियों पर भी विचार करने की अनुमति देता है, तो सुनवाई का अधिकार निहित हो सकता है। लेकिन यदि मूल्यांकन अकादमिक प्रदर्शन तक ही सीमित है, तो सुनवाई का अधिकार इतना निहित नहीं हो सकता है। निःसंदेह, यदि पूर्वाग्रह या दुर्भावना के आरोप हैं तो अलग-अलग विचार प्रबल हो सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह या दुर्भावना के आरोपों के अभाव में हम यह नहीं सोचते हैं कि किसी शैक्षणिक निकाय द्वारा यह घोषणा कि किसी छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन असंतोषजनक है, जिम्मेदार है। इस आधार पर अदालत में पूछताछ की जाएगी कि छात्र को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। बड़ा और विस्तारित, शायद सही ही, क्योंकि प्राकृतिक न्याय और असफल व्यवहार का क्षेत्र आवश्यक और स्वस्थ है, क्योंकि 'सुनवाई' आंशिक रूप से अकादमिक निकायों द्वारा भी प्रभावित होती है, ' कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दंडनीय घोषित नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिलता' के सिद्धांत के अप्राकृतिक विस्तार के प्रयास की सीमाएं हैं"। अकादमिक मामलों में भी अकादमिक अधिकारियों को निरपेक्षता दिए बिना, हमारा मानना है कि इस मामले में शायद ही न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रेजिन बनाम एस्टन यूनिवर्सिटी सीनेट पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया कि विश्वविद्यालय का परीक्षा निकाय किसी छात्र को परीक्षा में असफल होने पर विश्वविद्यालय

से हटने की आवश्यकता से पहले एक अवसर देने के लिए बाध्य है। बेशक, उस मामले में, परीक्षकों ने "बाहरी कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किया, जिनमें से कुछ की प्रकृति, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याएं केवल स्वयं छात्रों को ही ज्ञात हो सकती हैं"। इसलिए, डोनाल्डसन न्यायाधिपति ने कहा कि सामान्य निष्पक्षता से छात्रों को एक अवसर दिया जाना चाहिए था। फिर भी, लॉर्ड पार्कर मुख्य न्यायाधिपति, डोनाल्डसन न्यायाधिपति के दृष्टिकोण की शुद्धता और हेरिंग बनाम टेम्पलमैन और अन्य (उपरोक्त)के मामले में आश्वस्त नहीं दिखे, अपील में न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि डोनाल्डसन न्यायाधिपति की राय पर भविष्य के कुछ उपयुक्त अवसरों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

तथ्यों के पहले के विवरण से यह देखा जा सकता है कि प्रतिवादी ने पहले तीन सेमेस्टर में कोई भी मुख्य पाठ्यक्रम पास नहीं किया था। यदि किसी निश्चित विषय में एम.ए. की डिग्री के लिए कोई उम्मीदवार पहले तीन सेमेस्टर में उस विषय में किसी एक मुख्य पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो निश्चित रूप से, कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता है कि जिस शैक्षणिक निकाय ने उम्मीदवार के शैक्षणिक प्रदर्शन को असंतोषजनक घोषित किया है, ऐसी घोषणा करने में मनमाने ढंग से उसने कार्रवाई की है। हालाँकि, प्रतिवादी की शिकायत यह थी कि वह पहले दो सेमेस्टर में 'मुख्य पाठ्यक्रम' पास करने में असमर्थ था क्योंकि विश्वविद्यालय के अधिकारी कक्षाएं लेने के लिए शिक्षक उपलब्ध कराने में

विफल रहे और यह एक ऐसा कारक था जिसे विश्वविद्यालय के अधिकारी पूरा करने में विफल रहे थे। इसलिए, विचार करें और अधिकारियों को यह मानना चाहिए कि उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले सेमेस्टर में प्रतिवादी देर से विश्वविद्यालय में शामिल हुआ और कई कक्षाएं छूट गईं। परिणाम यह हुआ कि जबकि बाकी छात्रों ने रूसी भाषा में पर्याप्त प्रगति की थी, उत्तरदाता जिसने अभी तक वर्णमाला नहीं सीखी थी, वह सीधे मुख्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले बाकी छात्रों में शामिल नहीं हो सका। इसलिए, उन्हें रूसी भाषा की अन्य कक्षाओं में भाग लेना पड़ा जहाँ रूसी भाषा को 'मुख्य विषय' के रूप में नहीं बल्कि 'उपकरण या वैकल्पिक विषय' के रूप में पढ़ाया जाता था। प्रतिवादी के अनुसार 6 अक्टूबर 1974 और 6 दिसंबर 1974 के बीच उनके समूह को रूसी भाषा सिखाने वाला कोई नहीं था। फिर, दूसरे सेमेस्टर में, हालांकि 10 फरवरी से 30 मार्च, 1975 तक रूसी कक्षाएं थीं, लेकिन 30 मार्च के बाद अपने समूह को रूसी भाषा सिखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी । उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के इस आरोप को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने में विश्वविद्यालय की विफलता को बहुत महत्व दिया कि 6 अक्टूबर और 6 दिसंबर, 1974 के बीच और फिर 10 फरवरी और 30 मार्च, 1975 के बीच कोई शिक्षण सुविधाएं नहीं थीं। यह सच है कि विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में आरोपों से इनकार करें। लेकिन विश्वविद्यालय ने

अपने जवाबी हलफनामे में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया। पैराग्राफ 5 में कहा गया था:

> "वह 22 अगस्त 1974 को पहले सेमेस्टर में शामिल हुए, हालांकि यह 9 अगस्त 1974 से शुरू हुआ था। इतना ही नहीं, उन्हें उन छात्रों के साथ समूहीकृत किया जाना था, जिन्होंने रूसी को एक गैर-मुख्य विषय के रूप में पेश किया था और जिनके लिए रूसी कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हुईं फिर, 8 अक्टूबर 1975 से 20 दिसंबर 1975 तक, उनकी उपस्थिति नियमित नहीं थी। प्रतिवादी विश्वविद्यालय एक विशेष छात्र के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम कैसे वहन कर सकता है जो शिक्षण के नियमित पाठ्यक्रम का लाभ नहीं उठाता है विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के एक वर्ग के लिए? इसमें विश्वविद्यालय की कोई गलती नहीं है यदि याचिकाकर्ता कक्षाओं के संचालन के दौरान उपस्थित नहीं हो सका, और याचिकाकर्ता को उसकी अनियमित उपस्थिति के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए।"

पैराग्राफ 9 में फिर से कहा गया:

> "पैराग्राफ 9 के जवाब में, मैं कहता हूं कि याचिकाकर्ता 9 अगस्त 1974 को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जब मुख्य

विषय के रूप में रूसी की कक्षाएं शुरू हुईं। जब याचिकाकर्ता 22 अगस्त 1974 को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए आया, तो जिन छात्रों ने पेशकश की थी रूसी को एक मुख्य विषय के रूप में और 9 अगस्त को अपनी कक्षाएं शुरू करने से काफी प्रगति हुई है। याचिकाकर्ता, रूसी भाषा में नौसिखिया होने के कारण, उनमें से किसी भी समूह में समायोजित नहीं किया जा सका। इसलिए, उन्हें उन छात्रों के साथ समूहीकृत किया जाना था जो ने पेशकश की थी कि रूसी कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी।"

इन बयानों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय ने 'मुख्य पाठ्यक्रमों' के लिए आवश्यक कक्षाएं चलाईं, लेकिन प्रतिवादी रूसी भाषा के अपने अपर्याप्त ज्ञान के कारण उनका लाभ उठाने में असमर्थ था, जिस कारण से उसे 'वैकल्पिक' पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाओं में भाग लेना पड़ा, मुख्य पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के बजाय। विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूप से किसी एक छात्र के लिए विशेष कार्यक्रम नहीं चला सकता। इन बयानों पर उच्च न्यायालय का ध्यान नहीं गया। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विश्वविद्यालय के अधिकारी इस परिस्थिति से बेखबर थे कि विश्वविद्यालय स्वयं रूसी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है और इसलिए, इसे लागू नहीं माना जाना चाहिए। उनका दिमाग तथ्यात्मक आधार विहीन है।

इसलिए, हमारे पास अपील की अनुमति देने और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम यह जोड़ सकते हैं कि हम, किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का आभासी पुनर्लेखन शामिल है। अपील को स्वीकार करते हुये हम यह विचार करने के लिए विश्वविद्यालय पर छोड़ते हैं कि क्या प्रतिवादी के करियर को अध्यादेशों के अनुसार कुछ उचित सेमेस्टर में प्रवेश देकर बचाया नहीं जा सकता है, यदि वह प्रवेश के लिए आवेदन जमा करना चाहता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सिविल विविध याचिका संख्या 1926/1980 खारिज की जाती है।

एन.वी.के.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।